have been launched about Vehicular pollution.

(iii) The Petroleum Industry has been asked to reduce the lead content in petrol and bring it down to 0.15 gramme per litre.

(iv) The manufacturers have been asked to give a certificate to the effect that the exhausts from the vehicles are within the prescribed limits.

(v) The Ministry of Environment and Forests has asked the Ministry of Industry to issue instructions to all the vehicles manufacturers for making necessary changes in the design of vehicles for compliance of the prescribed standards.

(c) and (d) The State Boards have been provided funds for the purchase of instruments through a centrally aided scheme. These instruments also cover the types used for monitoring of automobile emissions. Under this scheme, the Central Government has released Rs. 1.59 Crores in 1989-90.

(e) and (f) The Directorate of Transport of the State Governments are charged with the responsibility of implementing the Motor Vehicles Rules, 1989.

मध्य प्रदेश में ओरिएन्ट पेपर मिल द्वारा सोन नदी को प्रदूषित किया जाना

2359. **श्री अजीत जोगी :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओरिएन्ट पेपर मिल्स, अमलई जिला शाहडोल, मध्य प्रदेश द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपायों के समुचित प्रबन्धन किये जाने के कारण सोन नदी काफी प्रदूषित हो गई है तथा जिसके फलस्वरूप नदी के आसपास के गांवों के निवासियों के जीवन तथा स्वास्थ्य पर गम्भीर प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा क्या पहल की जा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) दि ओरिएन्ट पेपर मिल्स, अमलई, मध्य प्रदेश ने एक बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित कर लिया है । लेकिन रंग छुड़ाने की सुविधा की व्यवस्था नहीं की है । इसके बहिस्राव सोन नदी में गिराये जा रहे है। इस नदी के आस-पास रहने वाले ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर बहिस्रावों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) केन्द्र सरकार ने कागज और लुगदी उद्योग सहित अत्याधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए एक विशेष अभियान चलाया है ताकि एक निश्चित समय के भीतर प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए संगठित कार्रवाई की जा सके ।

वन सम्पदा पर आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल

2360. **श्री अजीत जोगी :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चा माल न मिलने के कारण वन सम्पदा पर आधारित उद्योगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या पहल की गई है; और

(ग) क्या सरकार ऐसे उद्योगों को, विशेषकर शुष्क तथा बंजर भूमि में, वृक्ष उगाने के लिए पट्टे पर भूमि देने पर विचार कर रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख)

वनों के संरक्षण और सुरक्षा तथा पारिस्थितिक और पर्यावरणीय स्थिरता की जरूरत के कारण वनों पर आधारित उद्योगों को कच्चे माल की उपलब्धता पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में कहा गया है कि वनों पर अधारित उद्योगों को अपने कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करने के लिए जहां तक सम्भव हो, अधिमानतः फैक्टरी और कच्चा माल पैदा करने में सक्षम व्यक्तियों के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित करके कच्चा माल पैदा करना चाहिए।

(ग) उद्योगों को वृक्ष लगाने के लिए वन भूमि पट्टे पर देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय को वित्तीय सहायता

2361. **श्री अजीत जोगी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को दी जा रही वित्तीय सहायता दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की तुलना में कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं तथा इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के संस्थागत अवस्थापना को सुदृढ़ करने के लिए विकास अनुदान प्रदान करता है जैसे भवन, पुस्तक और पत्रिकायें, उपस्कर और अन्य सुविधायें जो अध्यापन और अनुसंधान की कोटि और स्तर को प्रोन्नत करने के लिए तैयार की गई हैं। आयोग विशेष सहायता की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भी अनुदान प्रदान करता है। विश्वविद्यालयों और कालेजों को इस बात पर ध्यान दिये बिना कि ये किन राज्यों से संबंधित हैं इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार अनुदान दिये जाते हैं। सहायता की राशि छात्रों के नामांकन अध्यापकों और अध्यापन विभागों की संख्या और इसके विकास के स्तर पर निर्भर करती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों और कालेजों की तुलना में मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान देने में, कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है।

मध्य प्रदेश में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई रेल परियोजनाएं

2362. **श्री अजीत जोगी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1989-90 में मध्य प्रदेश में रेलवे से संबंधित किसी परियोजना को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस अवधि के दौरान किसी अन्य राज्य के रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) रेलवे परियोजनाओं का अनुमोदन राज्यवार नहीं करके अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है। वर्ष 1989-90 के दौरान योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित रेलवे परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था :